THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting you. Please take your seat. (*Interruptions*)... If there are other Ministries' questions which are as important to some Members as the banking questions, we have to take those questions also. (*Interruptions*).. Mr. Gurudas Das Gupta, I know you seek my protection all the time. I must give protection to Mr. V. Hanumantha Rao. Question No. 323.

Permission for closure of Textile Mills

*323. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of textile mills which have sought permission to close down in the country;

(b) what is the reaction of his Ministry in this regard;

(c) how many such mills are located in Andhra Pradesh, together with the details of ownership and location; and

(d) whether any long term strategy is planned in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Permission for closing down of textile mills under the Industrial Disputes Act is given by the respective State Governments. As per available information no cotton/man-made fibre mill has been closed under the I.D. Act.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Government have set up a Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) to evolve and manage Rehabilitation Packages in respect of viable sick/closed mills.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Madam Deputy Chairman, is it a fact that as against 896 spinning mills and 270 weaving mills, only 72 spinning and 57 weaving mills were closed down? If yes, what is the number of weavers who have become unemployed and what are the arrangements made by the Government to rehabilitate the workers?

SHRI G. VENKAT SWAMY: Madam, the total number of cotton/man-made fibre mills is 1166. Public sector, that is, NTC and STC, is 188; co-operative is 121; private is 857. The total number of textile industries in India is 1,166. The number of mills before the BIFR up to 1994 is 262. The number of mills closed is 127 and the number of mills under liquidation is 29. The number of workers in closed mills is 1,73,000. The number of mills closed in AP is nil. The total number of workers affected is 3296. The number of mills of AP before the BIFR is 50.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Madam, I would like to know whether lay-off compensation is paid to them or any money has been paid to them from the National Renewal Fund. If so, what is the quantum of money paid to the workers and the total number of such workers to whom assistance from the National Renewal Fund has been given? I would like to know whether wages are being paid to idle workers in the closed NTC mills. If so, how many of them have been paid the idle wages and what is the amount paid per month or per year?

SHRI G. VENKAT SWAMY: We are implementing the VRS scheme only in NTC mills.

इसके तहत 33,000 वरकर्स गये है । एन० टी० सी० मिल्स का जो टारगेट है, सरप्लस वरकर्स का, वह अभी भी वरकर्स के लिये चालू है । वह जायेंगे । मगर यह कि कितना मिलेगा, यह उनकी सर्विस के लिहाज से मिलेगा । वे लोग सहूलियत के हिसाब से वी० आर० एस० स्कीम के तहत जा रहे है ।

SHRI V. HANUMANTHA RAO: How many workers are affected in the State? (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Both are coming from the same State. He can tell you later. (*Interruptions*)...

DR. NAUNIHAL SINGH: Madam, will the hon. Minister be pleased to state whether it is true that the textile industry will have to fork out an all-time high of Rs. 1,356 crores as excise during 1994-95, which is Rs. 1,141 crores more than the Rs. 215 crore revenue projected in the Budget, 1994-95 to be collected from

the textile industry? Will such a situation result in the closure of several textile mills? If so, what steps have the Ministry taken to avert it?

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभापति महोदया, आनरेबल मेम्बर ने जो क्वेश्चन किया है और जो प्रोसेस उन्होंने बताया है, उसके मामले में गवर्नमेंट आफ इण्डिया पटिकुलरली मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल जरूर एक्शन लेगी ।

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Madam, the Government's stand seems to be no closure, minimum merger and only modernisation. I really compliment the Government for coming up with a beautiful revival scheme, modernisation scheme, with an outlay of Rs. 2005 crores. As far as the new revival package is concerned, machinery worth Rs. 1200 crores will be procured from abroad against the suppliers' credit and the remaining Rs. 800 crores will be procured through the sale of surplus land belonging to the NTC mills. As I said earlier, it is a very good scheme, a very good package. However, I have my own doubts about the sale of surplus land. A lot of hurdles will be faced by the Government when they approach the State Governments to get permission for the sale of surplus land. A lot of surplus land of the NTC mills is situated in Mumbai. I for one I am opposed to the sale of surplus land for commercial purposes. Considering the amount of pollution, congestion and unhygienic conditions prevailing in Mumbai, it is not possible to overcome these hurdles. I would like the Minister to respond to this aspect of sale of surplus land. Part (b) of my question is...

उपसभापति : इतना लम्बा सवाल पूछेंगे तो दूसरे लोगों का सवाल नहीं होगा ।

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Presently the textiles industry is facing a crisis because of the hike in the excise and customs duties. The prices of yarn and cotton have gone sky-high because of the export of five lakh bales of cotton to various countries. It is my earnest request to the Government to reduce the excise and customs duties so that the present crisis can be overcome.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It should have been addressed to the Finance Minister.

श्री जी० वेंकटस्वामी : आप जानते है कि 122 एन० टी० सी० मिल्ज के बारे में आनरेबल मैम्बर का ख्याल है कि आपने माडर्नाइजेशन का प्लान सबमिट किया है । यह सही है कि ट्राइपार्टाइट कमेटी में सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ने मिल कर चंद जगह जा कर देखा है । मैं आनरेबल मैम्बर्स को यह बताना चाहता हूँ कि 100, 120, 128 साल पुरानी मशीनरीज से एन० टी० सी० मिल्ज चला रही हैं, अब नहीं चल सकती है । इसके साथ-साथ सरप्लस वर्किंग क्लास भी है जिसकी वजह से एन० टी० सी० को 3300 करोड़ का लॉस हो चुका है । यह बाते हमने ट्राइपार्टाइट कमेटी के सामने रखी और उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इसके ऊपर गौर किया । उसके बाद ट्राइपार्टाइट कमेटी में जो पी० आर० एस० ने प्लान दिया उसके लिहाज से माडर्नाइजेशन प्लान 2005 करोड़ का बना है । मैं आनरेबल मैम्बर्स को यकीन दिलाना चाहता हूँ ट्राइपार्टाइट कमेटी की रिपोर्ट जो पास हुई है उसको मैं केबिनेट के सामने रख कर प्रेक्टिकली इन सारी मिलों को माडर्नाइजेशन की तरफ ले जाऊंगा । अब रहा यह कि आखिर में उन्होंने कहा कि यार्न प्राइसेज बढ़ने की वजह से वीवर्ज को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए वीवर्ज को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है । यह सही है कि हमने कपास को ओ० जी० एल० के तहत इम्पोर्ट करने के लिए दिया है और इम्पोर्ट के अलावा हमने और भी बहुत सारे एक्शंस लिये हैं । वह दूसरा क्वेश्चन है । जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं आनरेबल मैम्बर्स को तफसीली जवाब दूंगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने जो कहा है, वह उस समझौते की ओर ध्यान दिला रहे है जो इसी साल 9 अप्रैल, 1994 को मिनिस्ट्री आफ लेबर के साथ यूनियंस का हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि एन० टी० सी० की कोई भी मिल बंद नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार का रिट्रेचमेंट नहीं होगा । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह समझौता इसी महीने 9 तारीख को हुआ है, इसको आप पूरा कब तक करेंगे ? नम्बर दो, इसी का हिस्सा है । इसका मतलब यह है कि जितनी भी एन० टी० सी० के बाहर प्राइवेट कारखाने है उन्हें जिन्दा रखने या खत्म करने का सवाल है लेकिन एन० टी० सी० मिलों को बन्द करने का सवाल नहीं है । आपकी लेबर मिनिस्ट्री ने बराबर यह कहा है, आपकी फॉरमल जिम्मेदारी, है आप इसको केबिनेट से पास करवा लें । तो बी० एफ० आई० आर० के अंदर आपने शायद बताया है कि 264 का सवाल है । मैं उसका नाम नहीं जानता जो आपकी बी० आई० एफ० आर० मशीनरी तय करती है, आपरेटिंग मशीनरी, तो बी० आई० एफ० आर० को जो रेफर हुए है, उसमें

से किसने में आपरेटिंग मशीनरी आपने नियुक्त कर ली है और वह रिपोर्ट कब तक देने वाली है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभापति जी, बी० आई० एफ० आर० का रिप्लाई तो मैं नहीं दे सकता, वह एक अदालत है, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि 266 टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनके सामने है और वह सोच-विचार कर रही है और जहां-जहाँ भी एक्शन लेना है बी० आई० एफ० आर० डायरेक्शन दे रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि इसके माडर्नाइजेशन के लिए आप कोई प्लान दे सकते हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उसके बीच का हिस्सा आप भूल रहे है, उसकी जानकारी मुझे चाहिए । बी० एफ० आई० आर० जब कि डायरेक्शन देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को, उसके पहले वह एक मशीनरी तैयार करती है, तो वह रेफर करती है बी० एफ० आई० आर० को कि इसकी स्थिति यह है कि यह रिहेबिलिटेट हो सकती है या नहीं । तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह मशीनरी कितनी बना दी गई है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : आनरेबल मैम्बर का क्वेश्चन मैं खुद नहीं समझ सका हूँ, जरा दोबारा समझाएं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरा सवाल यह है कि जब बी० एफ० आई० आर० के पास कोई जाता है तो बी० एफ० आई० आर० खुद यह नहीं कहती कि यह कर दो या न करो । वह किसी कम्पनी को या कोई मशीनरी तैयार करती है जो कि इन्वायरी करती है, उस कारखाने में जाकर उसकी रिपोर्ट को देखती है । वह बीच की मशीनरी कितनी जगह कायम हुई है ? आपको शायद प्रोसेस नहीं मालूम है ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : मुझे प्रोसेस मालूम है, मैं आपकी इन्फरमेशन के लिए कह सकता हूं कि बी० एफ० आई० आर० के पास आटोमेटिकली रेफर होता है अगर इंडस्ट्री कंटीन्यूअसली दो साल रहे, हमें रेफर करने की जरूरत नहीं है आटोमेटिकली बी० एफ० आई० आर० के सामने चले जाते है । ऑनरेबल मैम्बर को मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बी० एफ० आई० आर० के सामने इंडस्ट्रीज हैं, वे बहुत अच्छी तरह से उस पर ध्यान दे रहे है और जाँच-पड़ताल कर रहे है और जाँच-पड़ताल करने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के . . . (व्यवधान) . . .

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Either he has not understood the question or he is evading it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Minister is saying that the industries which are sick do not go through his Ministry. They go directly to the BFRI . . . . (*Interruptions*) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बी० एफ० आई० आर० में जाने के बाद एक मशीनरी तैयार करती है कि वह इंवायरी करे ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैडम, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश से, विशेष तौर पर जो हमारी औद्योगिक राजधानी है—कानपुर, वहां से कितने मिल ओनर्स ने अपनी मिलों को बंद करने की आपको दरखास्त दी है ? दूसरे, वहाँ अब तक कितनी मिलें बंद है, कितने मजदूर प्रभावित है और उनका रिहेब्लिटेशन करने के लिए आप तुरंत क्या करने जा रहे है ?

दूसरी बात माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, अभी आपने कहा है कि कुछ करोड़ रुपए आपने उनके रिहेब्लिटेशन का प्रावधान किए जाने के संबंध में अंकित किए है, मैं जानना चाहूंगा कि कानपुर की हमारी जो मिलें बंद है, उनको रिवाइव करने के लिए, उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आप क्या करने जा रहे है और क्या कोई आप ऐसा प्रयास कर रहे है, क्योंकि कई डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के आपसे मिले है, तो क्या आप कोई ऐसा प्रयास जल्दी से जल्दी करने जा रहे है कि वे मिलें खुले क्योंकि करोड़ो रुपए की लागत से जो मशीनें वहां लगी हुई है वे खराब हो रही है और इससे राष्ट्र की सम्पत्ति और धन का नुकसान हो रहा है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : आनरेबल मैम्बर को मैं बताना चाहूंगा कि पहले से ही खराब है, 100 साल के ऊपर की मशीनरी है और उन सबको इस ट्राइपार्टाइट कमेटी की रिकमेंडेशन में आनरेबल मैम्बर को मैं इन्फारमेशन देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे माडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे है और माडर्नाइजेशन होगा और वहां की वर्किंग क्लास को आज आइडियल वेज दे रहे है और आइडियल वेज देते हुए उस फैसले को रखा है । गवर्नमेंट आज भी उनको बैठाकर तनख्वाह दे रही है, जरा इसका भी ख्याल कीजिए और साथ ही साथ हम केबिनेट के सामने ट्राइपार्टाइट कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इसको माडर्नाइजेशन के रास्ते पर बहुत जल्दी से डालेंगे।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं जानना चाहूंगा कि आप कानपुर के लिए क्या कर रहे है ? जो धन आपने अंकित किया है, उसमें क्या उत्तर प्रदेश को कोई धन देने जा रहे है ? यदि देने जा रहे है तो वह कितना है या अभी वह प्रोसेस में है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं आनरेबल मेम्बर को यही बताना चाहता हूँ कि 122 मिल्स कानपूर की भी शामिल हैं ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, by the end of March, the Government spent Rs. 11,035 crores for modernising the mills in the private sector as well as the public sector. I would like to know as to how many of them are actually working now and what are the number of mills. both in the private sector and the public sector, for which the modernisation fund has been given.

SHRI G. VENKAT SWAMY : The Government sanctioned Rs. 750 crores for modernisation programme and this was allotted to the mills in the private sector as well as in the public sector. A large number of mills have taken this loan. This fund was created in 1st August, 1986. This amount of Rs. 750 crores was disbursed by the Government of India through the IDBI. Altogether, a sum of Rs. 877.94 crores was disbursed for modernisation of the mills.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, I wanted to know as to how many of them are actually working and how many of them are not working even after modernisation.

SHRI G. VENKAT SWAMY : As I mentioned, around Rs. 877 crores were allocated for modernisation of the textile mills and all the mills are operating now.

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे : मैडम, एन० टी० सी० में एक तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, बी० आई० एफ० आर० में फाइनेस डिपार्टमेंट है, फिर हर स्टेट में स्टेट्स के कन्सर्न होते हैं । जब भी रिनोवेशन और माडर्नाइजेशन की स्कीम एप्रूव कर देते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार माडर्नाइजेशन हो गया तो ये मालिक लोग कामशियलाइज करते है और कामशियलाइज करके वहां की जो प्रापर्टी है वह बेचने का उनका प्रयास होता है । सभी उसी तरह से फिर दिवाला निकालते हैं और फिर दुबारा वह प्रापर्टी या वह मिल लास में आती है । इसलिए क्या आपके पास ऐसी कोई मानीटरिंग एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, एन० टी० सी० की और फाइनेंस की, इतना ही मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : ऐसी कोई स्कीम प्राइवेट सेक्टर के माडर्नाइजेशन के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में तो नहीं है । आलरेडी एन० टी० सी० मिल्स को हमने लिया है, जिसको डिपारटाइट कमेटी ने एप्रो किया । उसको हम कैबिनेट नोट बनाने के बाद टेक्सटाइल, एन० टी० सी० मिल्स के लिए जायेंगे । मगर प्रायवेट मिल्स के माडर्नाइजेशन के लिए जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम 750 करोड़ रुपीज हमने रखा था । वह जो हुआ है उसमें वे सारी की सारी अच्छी चल रही है । रहा यह कि चंद लोग, प्रायवेट मिल ओनर्स—और असल क्वेश्चन हमारे शिन्दे जी का यही है कि वे माडर्नाइजेशन के नाम पर प्रापर्टीज को, सरप्लस लैंड को बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कोई कानून नहीं है । मगर स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है ।

Doordarshan Kendra at Bhubaneswar

*324. SHRI SARDA MOHANTY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bhubaneswar, the Capital of Orissa, is the only State Capital in the country having no Dooardarshan Kendra; and

(b) if so, by when Government of India porpose to instal Doordarshan Kendra at Bhubaneswar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) No, Sir. A Doordarshan Kendra is operating at Bhubaneswar Since 19-11-1992.

(b) Does not arise.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

यू० एन० ट्रस्ट फंड के लिए सहायता

***श्री राम गोपाल यादव :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० ट्रस्ट फंड के अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं को काम देने हेतु केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता की मांग की है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है ;